यूपी बनेगा बायोडीजल उत्पादन का केंद्र, 30 कंपनियां हैं तैयार

चंद्रभान यादव

लाइसेंस नीति से हर जिले में बढ़ेंगे उत्पादन और बिक्री केंद्र

लखनऊ। उत्तर प्रदेश बायोडीजल उत्पादन का केंद्र बनेगा। इसके लिए 30 कंपनियां तैयार हैं। कई ने आवेदन कर रखा है। लाइसेंस नीति तय होते ही इनकी संख्या में तेजी से इजाफा होगा। उत्पादन के साथ ही बिक्री के लिए हर जिले में केंद्र खुलेंगे। इससे एक तरफ रोजगार बढ़ेगा तो दूसरी तरफ प्रयोग किए गए खाद्य तेलों का नए सिरे से प्रयोग हो सकेगा। अभी यूपी में रोजाना करीब 200 किलोलीटर बायोडीजल तैयार होता है।

जैव ऊर्जा नीति 2022 में बायोडीजल को बढ़ावा देने की व्यवस्था बनाई गई है लेकिन लाइसेंस संबंधी व्यवस्था नहीं होने से उत्पादन व बिक्री केंद्रों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। क्योंकि केंद्र सरकार ने वाहनों के लिए हाई स्पीड डीजल के साथ बायो डीजल को मिलाकर बेचने का निर्देश दिया है लेकिन बायोडीजल उत्पादन व बिक्री संबंधी

रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जले खाद्य तेलों का होगा सदुपयोग

लाइसेंस देने का अधिकार राज्य का है। मंगलवार को राज्य सरकार ने लाइसेंस जारी करने के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर दिया है।

ऐसे में बायोडीजल के क्षेत्र में तमाम कंपनियां आगे आएंगी। अभी 30 कंपनियां विभिन्न स्थानों पर बायोडीजल उत्पादन के लिए प्लांट लगा रही हैं। अब इन्हें उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (यूपीनेडा) उत्पादन संबंधी लाइसेंस जारी कर देगा। यहां उत्पादन शुरू होते ही करीब 750 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी तरह हर जिले में जिलाधिकारी के माध्यम से फुटकर बिक्री का लाइसेंस भी जारी किया जाएगा।

फुटकर बिक्री से हर केंद्र पर पांच को रोजगार

विभागीय अधिकारियों के मुताबिक हर फुटकर केंद्र पर करीब पांच लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। एक केंद्र स्थापित करने पर करीब 1.50 करोड़ रुपये निवेश होगा। बायोडीजल की फुटकर बिक्री बढ़ने से किसानों को भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा। वहीं, महुआ, नीम, करंज, अरंडी आदि की खेती को बढ़ावा मिलेगा। इनके बीज से निकलने वाला तेल बायोडीजल के रूप में प्रयोग किया जाएगा।

खाद्य तेलों का होगा सदुपयोग

एफएसडीए के उप आयुक्त हरिशंकर सिंह कहते हैं कि नई व्यवस्था से सेहत सुधार में अहम काम होगा। दुकानदार जले हुए तेलों को बार-बार प्रयोग नहीं करेंगे। जिन खाद्य तेल का टोटल पोलर कंपाउंड (टीपीसी) का मानक 25 या इससे अधिक होता है, उन्हें बायोडीजल में भेजने का निर्देश है। इसके लिए 57 जिलों में विशेष जांच अभियान चलता है। प्रदेश में इस तेल को इकट्ठा करने के लिए 665 आउटलेट बनाए गए हैं। रोजाना करीब 400 लीटर से ज्यादा तेल इकट्ठा होता है। नौ कंपनियां इस कार्य में लगी हैं। लाइसेंस प्रणाली जारी होने के बाद इनकी संख्या बढ़ेगी।

लाइसेंस नीति तय होने से प्रदेश में बायोडीजल का चलन बढ़ेगा। उत्पादन इकाइयां स्थापित होंगी और बिक्री केंद्र भी खुलेंगे। बायोडीजल में प्रयोग होने वाली वनस्पति जेट्रोफा व अन्य की खेती को भी बढ़ावा मिलेगा।

-अनुपम शुक्ला, निदेशक यूपीनेडा